

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।

कृषि एवं विपणन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में परम्परागत फसलों (मंडुवा, सांवा, रामदाना, भट्ट, राजमा, गहत) का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं० 5440/परम्परागत कृषि/2015-16 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 के क्रम में राज्य के पर्वतीय जनपदों में उत्पादित होने वाले परम्परागत उपजों के उत्पादकों को उनकी उपज का आपेक्षित मूल्य प्रदान किये जाने के उद्देश्य के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु राज्य में उत्पादित मंडुवा हेतु ₹० 1900.00 प्रति कु० (₹० 19.00 प्रति कि०ग्रा०), सांवा हेतु ₹० 1600.00 प्रति कु० (₹० 16.00 प्रति कि०ग्रा०), रामदाना हेतु ₹० 2250.00 प्रति कु० (₹० 22.50 प्रति कि०ग्रा०), भट्ट हेतु ₹० 2600.00 प्रति कु० (₹० 26.00 प्रति कि०ग्रा०), गहत हेतु ₹० 7200.00 प्रति कु० (₹० 72.00 प्रति कि०ग्रा०) की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करते हुए कृषकों से क्रय/उपार्जन किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : -

1. उपरोक्त उपजों की कुल अनुमानित मात्रा का कुल 3150 मै०टन अथवा वास्तविक मात्रा जो भी कम हो, के उपार्जन हेतु उपरोक्त घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार उपजों के उपार्जन/क्रय का कार्य अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं देहरादून में कृषि विभाग द्वारा स्थापित निर्धारित उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। सम्बन्धित जनपदीय केन्द्रों पर मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा यथोचित विभागीय कार्मिकों की तैनाती तथा मूलभूत व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाएगी। दोनों मण्डलों के मण्डलीय अधिकारी अपने मण्डल में इस पूरे कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

2. उक्त उपजों का उपार्जन कार्य 15 दिसम्बर, 2015 से 31 जनवरी, 2016 तक प्रभावी होगा।

3. क्रय किये जाने वाले परम्परागत उपजों के क्रय के मानकों का निर्धारण निदेशक कृषि अपने स्तर से जारी करेंगे। क्रय की जानी वाली उपज स्वस्थ, रोगरहित एवं ऐसी हो, जिससे कि उनकी पुनः बिक्री उचित मूल्य पर हो सके। क्रय के समय फसलों में मानकों के अनुरूप आर्द्धता का ध्यान रखा जाए।

4. उपार्जित फसलों का क्रय 25 कि०ग्रा० के बैग की उपयुक्त पैकिंग में किया जाएगा तथा पैक करने के उपरान्त उस पर उपज का नाम, क्रय केन्द्र का नाम, क्रय की तिथि आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा तथा उसके अल्पकालिक भण्डारण तथा परिवहन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी। उपार्जित उपजों का परिवहन कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 हेतु ढुलान की अनुमोदित दरों पर किया जाएगा, यदि विभाग द्वारा दरों का अनुमोदन नहीं हुआ है तो, उद्यान विभाग द्वारा अनुमोदित दरों अथवा उससे कम दरों पर परिवहन कार्य किया जाएगा।

5. उक्त उपार्जन एवं विपणन कार्य हेतु उपार्जन मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत अथवा क्रय हेतु आपेक्षित सुविधाओं के सृजन बारदाना, परिवहन एवं अन्य व्यय हेतु वास्तविक स्थितियों के अनुसार अनुमन्य होगी। समस्त व्ययों में मितव्ययता का विशेष अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

6. परम्परागत उपजों के उपार्जन एवं विपणन का कार्य कृषि विभाग के सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कृषि अधिकारियों एवं उद्यान विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद के सहयोग से किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपदों के मुख्य कृषि अधिकारी इस सम्पूर्ण कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे तथा मण्डलीय अधिकारियों की अध्यक्षता में गठित समिति के मार्गदर्शन में उपार्जित उपजों का विपणन परिषद के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। योजनान्तर्गत उपजों का क्रय/उपार्जन केवल कृषि विभाग द्वारा विकसित संकुल के पंजीकृत कृषकों हेतु प्रभावी होगा। ठेकेदार एवं बिचौलिए इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

7. योजनान्तर्गत परम्परागत फसलों के उत्पादक उपरोक्त घोषित समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिलने की दशा में वे अपनी फसल का विक्रय अन्य को करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

8. सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारी उपार्जन की जाने वाली परम्परागत फसलों का आंकलन कर क्रय हेतु धन की मांग निदेशक कृषि को एवं विपणन परिषद को यथासमय उपलब्ध करायेंगे, जिससे कि उनकी मांगानुसार उतनी धनराशि उपार्जन कार्य हेतु उन्हें उपलब्ध कराई जा सके।

9. उपजों के क्रय पर होने वाला व्यय शासन द्वारा कृषि विभाग को अथवा परिषद को उपलब्ध कराई गई चक्रीय निधि/निधि से वहन किया जाएगा तथा उपार्जित उपजों के विपणन से प्राप्त धनराशि इसी निधि में जमा की जाएगी।

10. कृषि विभाग द्वारा उपार्जित परम्परागत उपजों को भण्डारणोपरान्त राज्य के भीतर एवं राज्य के बाहर की मण्डियों को विक्रय किया जाएगा। यदि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य या इससे अधिक मूल्य स्थानीय बाजारों में प्राप्त होता है तो, इसे नीलामी द्वारा प्रथम प्राथमिकता पर विक्रय किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य अथवा राज्य के बाहर के प्रमुख क्रेताओं को सरकारी विभागों यथा—एकीकृत बाल विकास एवं पुष्टाहार (आई०सी०डी०एस०), पुलिस, जेल व अन्य विभागों को उनके द्वारा संचालित योजनान्तर्गत आपूर्ति की जाएगी। सम्बन्धित मुख्य कृषि अधिकारियों द्वारा उपजों के क्रय पर हुए व्यय एवं विक्रय से प्राप्त आय का पूर्ण विवरण निदेशक कृषि एवं विपणन परिषद को उपलब्ध कराया जाएगा तथा विक्रय से प्राप्त आय को निदेशालय अथवा परिषद की चक्रीय निधि (यथास्थिति) में तत्काल जमा किया जाएगा एवं सम्पूर्ण भुगतान प्रक्रिया एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से की जाएगी।

11. योजना के पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों की होगी। यदि कहीं भी फसल बिना समुचित देखभाल के खराब होती है, तो सम्बन्धित अधिकारियों से तदनुसार वसूली की जायेगी।

12. उक्त आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अर्द्ध०शा०प०स० 111(P) / XXVII(4) / 2015, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)  
प्रमुख सचिव

संख्या: २३५४ / XIII-1 / 2015-1(26)2015 टीसी-1 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबेराय मोर्टर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. महानिदेशक, पुलिस, उत्तराखण्ड।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं देहरादून।
5. महानिरीक्षक, जेल, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, एकीकृत बाल विकास एवं पुष्टाहार, देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डल बोर्ड, रुद्रपुर।
8. अपर निदेशक, कृषि विभाग, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
9. मुख्य कृषि अधिकारी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चम्पावत, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं देहरादून।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड औद्यानिक विपणन परिषद, देहरादून।
11. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विभाग विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
13. उद्यान अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
14. कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
/  
वा

(राजेन्द्र सिंह)  
संयुक्त सचिव